भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 369 का उत्तर

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

369. श्री संजय दीना पाटिल:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र के लिए घोषित की गई नई रेल-परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) इनमें से अब तक कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं और उनके लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है, तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उन परियोजनाओं की स्थिति क्या है जिन्हें चालू नहीं किया गया है और उन्हें कब तक चालू किया जाएगा;
(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र का एक बड़ा क्षेत्र अभी भी रेल संपर्क से वंचित है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य आरंभ होने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री संजय दीना पाटिल, श्री भास्कर मुरलीधर भगरे, श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल, श्री निलेश ज्ञानदेव लंके, श्री धैर्शशील राजसिंह मोहिते-पाटील, श्रीमती सुप्रिया सुले, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ और श्री बजरंग मनोहर सोनवणे के अतारांकित प्रश्न सं. 369 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल परियोजनाएँ राज्य-वार या क्षेत्रवार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत की जाती है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 81,580 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 5,877 किलोमीटर लंबाई की 41 परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) योजना बनाने और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,926 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक, 31,236 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इनमें शामिल हैः

- **(I) 38,423 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,017 किलोमीटर की कुल लंबाई की 16 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 166 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी हैं और मार्च 2024 तक 8,529 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।**
- **(II) 7,339 करोड़ रुपये की लागत वाली 609 किलोमीटर कुल लंबाई की 2 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 312 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक 3,332 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।**
- **(III) 35,818 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,251 किलोमीटर कुल लंबाई की 23 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 1,448 किलोमीटर लंबाई चालू की जा चुकी है और मार्च 2024 तक 19,376 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।**

इसके अलावा, उपनगरीय गलियारों पर भीड़भाड़ से बचने और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए 10,947 करोड़ रुपये की लागत पर एमयूटीपी-III और 33,690 करोड़ रुपये की लागत पर एमयूटीपी-IIIए को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित अतिरिक्त 10 रेल संपर्क शामिल हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ करोड़ में)
1	पांचवीं और छठी लाइन सीएसटीएम-कुर्ला (17.5 किमी)	891
2	छठी लाइन मुंबई सेंट्रल-बोरीवली (30 किमी)	919
3	पनवेल-करजत उपनगरीय गलियारा (29.6 किमी)	2782
4	ऐरोली-कलवा (एलिवेटेड) उपनगरीय कॉरिडोर लिंक (3.3 किमी)	476
5	विरार-दहानु रोड की तीसरी और चौथी लाइन (64 किमी) का चौहरीकरण	3587
6	हार्बर लाइन गोरेगांव-बोरीवली का विस्तार (7 किमी)	826
7	पांचवीं और छठी लाइन बोरीवली-विरार (26 किमी)	2184
8	कल्याण-आसनगांव के बीच चौथी लाइन (32 किमी)	1759
9	कल्याण-बदलापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन (14.05 किमी)	1510
10	कल्याण यार्ड-मेन लाइन और उपनगरीय लाइन का पृथक्करण	866

इन सभी एमयूटीपी परियोजनाओं को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच लागत भागीदारी के आधार पर 50:50 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार मार्च 2022-23 तक प्रतिबद्धता के अनुसार समय पर अपेक्षित धनराशि प्रदान नहीं कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2023 से एमयूटीपी-IIIए परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण शुरू कर दिया है।

2014 के बाद से, निधि आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और उसके अनुरूप भारतीय रेल में परियोजनाओं की कमीशनिंग भी हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली

अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है -

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान कमीशनिंग की तुलना में औसत वृद्धि
2009-14	₹1,171 करोड़/वर्ष	-
2014-24	₹7,197 करोड़	6.1 गुणा
2023-24	₹13,539 करोड़	11.56 गुणा

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की कमीशनिंग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किया गया कुल रेलपथ	कमीशन किया गया औसत रेलपथ	2009-14 के दौरान कमीशनिंग की तुलना में औसत वृद्धि
2009-14	292 कि.मी.	58.4 कि.मी./वर्ष	-
2014-24	1830 कि.मी.	183 कि.मी./वर्ष	3.13 गुणा

2023-24 में, कुल 358 किलोमीटर रेलपथ की कमीशनिंग की गई है, जो 2009-14 के दौरान की गई औसत कमीशनिंग की तुलना में 6 गुना अधिक है

किसी भी रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक क्लीयरेंस, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना(ओं) के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

*****